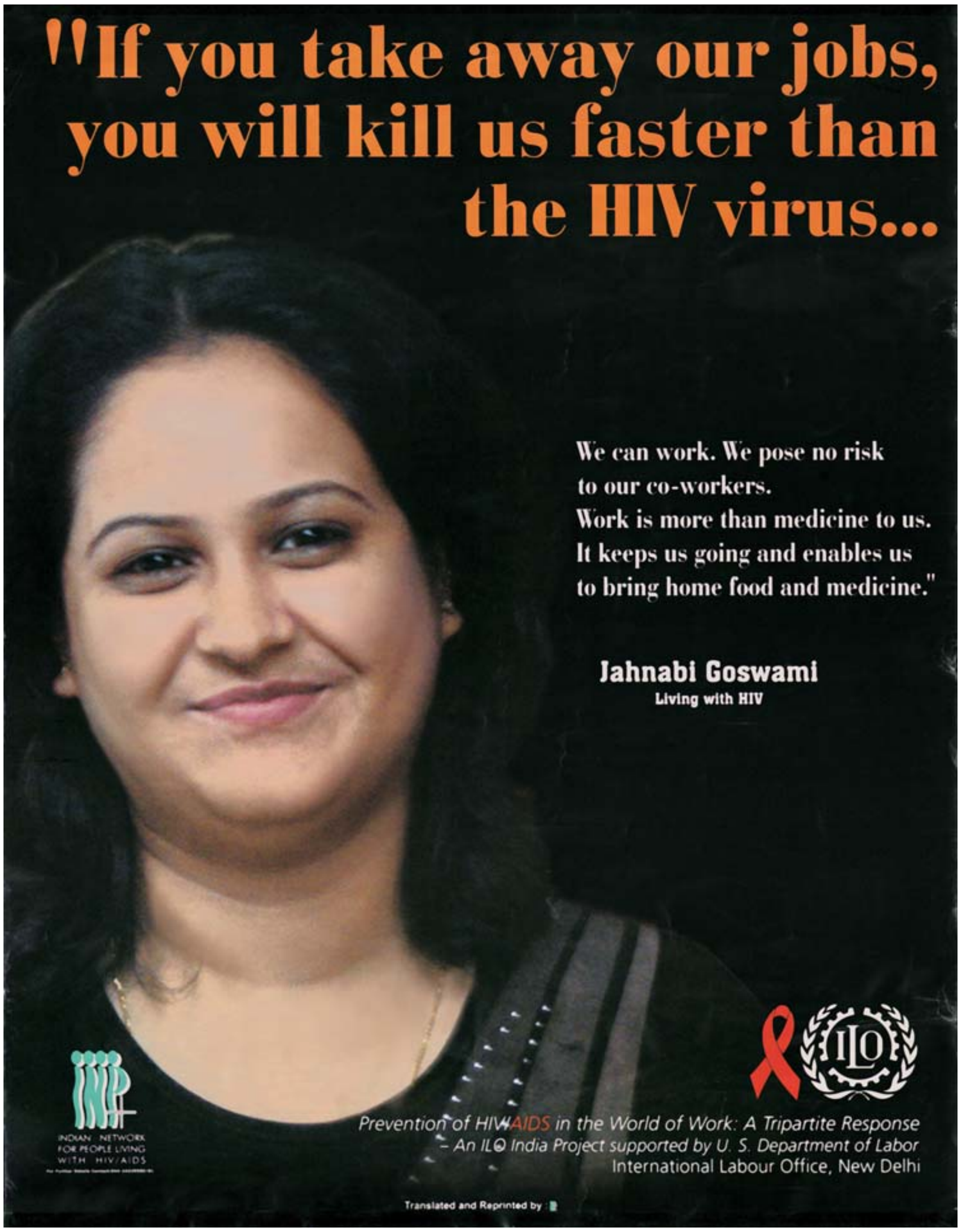
"If you take away our jobs, you will kill us faster than the HIV virus...
We can work. We pose no risk to our co-workers. Work is more than medicine to us. It keeps us going and enables us to bring home food and medicine."
Jahnabi Goswami
Living with HIV
INP+
INDIAN NETWORK FOR PEOPLE LIVING WITH HIV/AIDS
ILO
Prevention of HIV/AIDS in the World of Work: A Tripartite Response
– An ILO India Project supported by U. S. Department of Labor
International Labour Office, New Delhi
Translated and Reprinted by

एचआईवी/एड्स
मीडिया मैन्युअॅल
भारत 2007

3

प्रभाव तथा शासन

विवेकानंदन

एचआईवी/एड्स महामारी में समाजों तथा अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य को एक बड़े पैमाने पर बुरी तरह प्रभावित करने की क्षमता है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट, 2005 कहती है कि एचआईवी/एड्स ने मानव इतिहास में सबसे बड़ा विकासात्मक परिवर्तन किया है। सन् 1990 और 2003 के बीच, मानव विकास सूची में, एचआईवी/एड्स से सबसे बुरी तरह प्रभावित बहुत सारे देशों का वैश्विक दर्जा बहुत तेजी से नीचे गिरा है। दक्षिण अफ्रीका 35 स्थान, जिम्बाब्वे 23 स्थान, बोट्सवाना 21, स्वाज़ीलैण्ड 20, केन्या 18, जाम्बिया 16 और लिसोथो 15 स्थान नीचे गिरा है।

एचआईवी/एड्स कई क्षेत्रों में प्रगति को पलट सकता है। यह क्षेत्र जीवन प्रत्याशा से लेकर औद्योगिक उत्पादन तक अलग अलग हो सकते हैं। महामारी का प्रभाव ही है, जो उसके नियंत्रण को महत्वपूर्ण बनाता है।

जनसंख्या की संरचनाएं

महामारी के अगमन से पहले तक जीवन प्रत्याशा की ओर जो लगातार प्रगति हुई थी, अब वह बहुत बुरी तरह प्रभावित देशों में उलट गई है। बोट्सवाना ऐसा देश है, जहां उत्पादक पीढ़ी समाप्त हो चुकी है। 20 से 49 वर्ष आयु वर्ग के वयस्कों ने मृत्युदर में बहुत अधिक उछाल देखा है और पहले जो आयु अनुसार मृत्यु वितरण था, अब वह उलटा हो गया है। इस कारण से, 1985 और 1990 के बीच इस आयु समूह में कुल मृत्यु संख्या जो 20 प्रतिशत होती थी, आज लगभग 60 प्रतिशत है।

गरीबी और असमानता

जनसंख्या के अन्य समूहों की तुलना में एचआईवी/एड्स गरीबों को ज्यादा बुरी तरह प्रभावित करता है। बोट्सवाना में, यह अनुमान है कि औसतन महामारी के कारण अगले 10 वर्षों में कमाने वाले हर व्यक्ति पर एक अतिरिक्त आश्रित व्यक्ति होगा। लेकिन जनसंख्या के सबसे निर्धन चौथे हिस्से के

> 'जिन लोगों को दवा मिल सकती है उनके लिए एड्स मृत्यु का आदेश नहीं है। अब यह राजनीतिज्ञों पर है कि वे बीमारी के बेहतर इलाज के लिए 'व्यापक रणनीतियां' बनाएं'।
>
> – **बिल क्लिंगटन**
>
> भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रपति

कार्यस्थल पर कार्यवाही करना

आँध्र प्रदेश में सिंगरेनी कोयला खानें एक मुख्य नियोक्ता हैं और यह राज्य भारत के एचआईवी प्रसार की ऊँची दर वाले राज्यों में से एक है। देश में कोयले की 10 प्रतिशत पूर्ति करने वाली और 93,000 से भी अधिक लोगों को काम देने वाली कोयले की खान, ने महामारी के वर्तमान में और अपने कर्मचारियों तथा कार्यों पर संभावित प्रभाव पता लगाने की कोशिश की। यह अनुमान लगाने के बाद कि वर्तमान में कार्यबल का लगभग 2 प्रतिशत भाग एचआईवी+ (कुल स्थानीय जनसंख्सया से कुछ अधिक) था, अध्ययन ने आने वाले वर्षों में होने वाले विभिन्न खर्चों का हिसाब लगाया, इसमें दवा का खर्च, बीमा खर्च और मृत्यु या बीमारी की स्थिति में कर्मचारी के बदले किसी को रखने का खर्च शामिल था। अन्य जाँच–परिणामों के साथ, अध्ययन में पता चला कि यदि मज़दूरों का इलाज नहीं हुआ, तो अगले 10 वर्षों में बीमारी बढ़ने के साथ उनके मुआवजे का खर्च 21 मिलियन यूएस डॉलर पर पहुँच जाएगा। इसके विपरीत, इतने ही दिनों एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी प्रदान करने से – जिससे कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ेगा और वे अपने परिवार की देखभाल कर पाएंगें – उसमें केवल 1.24 मिलियन यूएस डॉलर का खर्च आएगा। इसके व अन्य जाँच–परिणामों के जवाब में, कम्पनी ने एचआईवी रोकथाम के विभिन्न उपायों को लागू किया है, और आजकल सरकार, यूनियनों तथा स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं के साथ एचआईवी+ मज़दूरों को उपचार व देखभाल प्रदान करने के विभिन्न विकल्पों को तलाश रही है।

— आईएलओ, 2005

परिवारों में आठ अतिरिक्त व्यक्ति जुड़ जाएंगें जो एचआईवी के परिणामस्वरूप उनकी आय पर आश्रित हो जाएंगें, ऐसा यूएनएड्स की वैश्विक एड्स महामारी रिपोर्ट, 2006 का कहना है। भारत में किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि गरीब, कम शिक्षित या अकुशल समूहों के परिवारों, साथ ही परिवारों की महिला सदस्यों को एचआईवी/एड्स के कारण अनुपात में अधिक आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है।

कलंक और भेदभाव

कलंक और भेदभाव महामारी के दो सबसे खराब परिणामों में से हैं। ये एचआईवी की रोकथाम और एचआईवी/एड्स के साथ जी रहे लोगों (पीपल लिविंग विद एचआईवी – पीएलएचए) के इलाज एवं देखभाल में भी रुकावट हैं। एचआईवी से जुड़े कलंक में उन लोगों की तरफ नकारात्मक सोच शामिल हैं जो एचआईवी से संक्रमित हैं या जिन पर संक्रमित होने का शक होता है। इनमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो एचआईवी/एड्स से किसी भी तरह से संबंधित हैं, जैसे कि अनाथ या बच्चे या फिर एचआईवी/एड्स के साथ जी रहे लोगों के परिवार। भेदभाव, जिसे यूएनएड्स की आचार–संहिता (प्रोटोकॉल) में एचआईवी/एड्स के साथ जी रहे लोगों के विरुद्ध भेदभाव पहचानने के लिए परिभाषित किया गया है, इसमें किसी भी तरह का अंतर, बहिष्कार या पाबंदियां शामिल हैं जो उन लोगों को प्रभावित करती हैं जिनकी एचआईवी+ स्थिति पता चल जाती है या शक होता है। एचआईवी से जुड़ा कलंक और भेदभाव विश्व के हर भाग में पाया जाता है, लेकिन अलग अलग जगहों में उनका स्वरूप भिन्न होता है।

स्वास्थ्य देखभाल

एचआईवी एक महंगा वाइरस है। एचआईवी के ऊँचे प्रसार वाले देशों में, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर महामारी का काफी गंभीर असर हुआ है। यह असर कई स्तरों पर होता है। सबसे पहले, उपलब्ध संसाधन घटने शुरू हो जाते हैं और टैक्स का आधार सिकुड़ता जाता है चूंकि समाज के सबसे अधिक उत्पादक हिस्से प्रभावित होते हैं। महामारी वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल संरचनाओं से निश्चय ही काफी बड़ी मांग कर रही है। उप–सहारा अफ्रीका में, एचआईवी से जुड़ी बीमारियों वाले लोग सभी अस्पतालों के आधे से अधिक बिस्तर घेरे रहते हैं।

शासन का संबंध

शासन क्यों

क्या – अच्छे या खराब – शासन का एचआईवी/एड्स महामारी से कोई लेना देना है?

पहली नजर में, इन दोनों के बीच किसी संबंध की अपेक्षा करना अस्वभाविक लगता है। लेकिन विशेषज्ञ और राजनीतिक वैज्ञानिक कहते हैं, दोनों आपस में करीब से जुड़े हुए हैं। आसान शब्दों में, वे कहते हैं कि एचआईवी/एड्स के प्रसार को नियंत्रित करने में सुशासन बहुमूल्य है, इसके विपरीत, खराब शासन संक्रमण और मृत्युदर को नियंत्रण से बाहर पैर फैलाने देता है।

तबाही मचा सकता है उसके कारण सुशासन महत्वपूर्ण है। माहमारी को अच्छी तरह न संभाला गया तो वह समाजों का सर्वनाश कर सकती है, वृद्धि को धीमा और जीवन प्रत्याश को बहुत तेजी से घटा सकती है। बहुत से अफ्रीकी देशों को खराब शासन के एकदम सही उदाहरणों के रूप में पहचाना गया है। सिक्के का दूसरा पहलू है कि युगांडा और थाइलैण्ड जैसे देशों ने दिखाया

islamicate.typepad.com

अधिकाधिक डोनर राष्ट्र और संस्थाएं सुशासन को एचआईवी/एड्स का सामना करने के लिए दिए जाने वाले फण्ड से जोड़ रही हैं। आंशिक रूप, से इसे फण्ड का सही प्रयोग सुनिश्चित करने के प्रयास और जिस कारण व व्यक्तियों के लिए यह दिया गया है उनके फायदे के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसके परे, सुशासन के सिद्धांत राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं।

शासन तथा एचआईवी/एड्स में संबंध

वैश्विक शासन पर गठित आयोग (1995) ने शासन को इस तरह परिभाषित किया ......'उन विभिन्न तरीकों का जोड़, जिनके द्वारा सार्वजनिक या निजी, वैयक्तिक एवं संस्थाएं अपने सामान्य मामलों को चलाते हैं'।

एचआईवी/एड्स जो कि व्यापक है कि रणनीतिक दूरदृष्टि और अर्थपूर्ण कार्यवाही से लहर को रोका या मोड़ा भी जा सकता है।

यूएनडीपी के एक अधिकारी, ली–नाह सू, ने निम्नलिखित 'विजय समीकरण' सुझाए हैं:

विकास + अच्छी शासन प्रणाली = निम्न और स्थिर एचआईवी प्रसार

इस अवधारणा को सही ठहराने के लिए उदाहरण ढूँढना मुश्किल नहीं है, भले ही इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

सरकार, आय और अपने नागरिकों के जीवन के आर्थिक विकास पहलुओं को संबोधित करके, एचआईवी के पीछे छिपे जोखिमों पर काम कर रही है। ये नागरिकों को ऐसे खतरे उठाने के लिए मजबूर करते हैं, कि अगर वातावरण उनके

अनुकूल होता तो अपनी आजीविका के लिए वे ऐसा नहीं करते।

उदाहरण के लिए, ग्रामीण प्रवासी मज़दूर, जिनका कौशल कृषि आधारित होता है, शहर में आने के बाद शायद उनके पास यौनकार्य के अलावा अधिक विकल्प नहीं होते। यदि उन्हें वैकल्पिक रोजगार या कौशल प्रशिक्षण दिया जाए, तो उन्हें शहर में आना ही न पड़े। इस तरह के रोजगार या कौशल प्रशिक्षण देने से मज़दूरों को एचआईवी/एड्स से जोखिम कम होगा और सुशासन स्थापित होगा।

www.tagstudio.net

सुशासन क्या है?

यूएनडीपी का कहना है सुशासन ''.. ......सहभागितापूर्ण, पारदर्शी और उत्तरदायी होता है। यह प्रभावकारी और न्यायसंगत होता है और यह विधि के शासन को बढ़ावा देता है। सुशासन यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक एवं आर्थिक प्राथमिकताएं समाज में व्यापक स्वीकृति पर आधारित हों और विकास संसाधनों के आवंटन की निर्णय–प्रक्रिया में समाज के सबसे गरीब और संवेदनशील की आवाज सुनी जाए''।

भारत में, हमारे पास अभी भी एड्स महामारी को रोकने का मौका है इससे पहले कि यह व्यापक रूप से फैल जाए और सर्वनाश कर दे, जैसा हम आज अफ्रीका में देखते हैं।

— अटल बिहारी वाजपेयी

भूतपूर्व भारतीय प्रधान मंत्री

सुशासन मात्र अच्छे शासन से कहीं अधिक है। क्योंकि यह नागरिकों द्वारा सरकार के सभी कार्यों की अच्छी समझ और उसकी संस्थाओं के प्रबंधन में साफ, सही और अनुकूल तरीकों से उनके जुड़ाव को लक्षित करता है, और मानव अधिकार एवं खुशहाली को प्रोत्साहित करता है। सुशासन समाज के हर स्तर पर लागू होता है।

दूसरी ओर, कमज़ोर शासन लगभग हमेशा भष्टाचार की छवि पेश करता है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की अनुपस्थिति में भ्रष्टाचार फलता–फूलता है। इस कारण, यह सुशासन के अन्य कारकों – विधि का शासन, समानता, उत्तरदायित्व निभाना और दूरदर्शिता – को बाधित करता है।

सुशासन के तत्व

भागीदारी : निर्णय–प्रक्रिया में हर महिला और पुरुष की आवाज होनी चाहिए, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली वैध मध्यवर्ती संस्थाओं के माध्यम से। ऐसी भागीदारी भाषण और संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ साथ रचनात्मक रूप से भाग लेने की क्षमता पर बनती है।

विधि का शासन : कानूनी ढाँचें उचित होने चाहिए और निष्पक्ष रूप से लागू किए जाने चाहिए, विशेषरूप से मानव अधिकार कानून।

पारदर्शिता : पारदर्शिता सूचना के मुक्त प्रवाह से बनती है। प्रक्रियाएं और संस्थाएं उनसे संबद्ध लोगों को सीधे सुलभ होती हैं और उन्हें समझने व उनके अवलोकन के लिए पर्याप्त जानकारी दी जाती है।

उत्तरदायित्व निभाना : संस्थाएं और प्रक्रियाएं सभी दावेदारों के काम आने का प्रयास करती हैं।

सर्वसम्मति अनुस्थापन : सुशासन, समूह और जहाँ संभव हो नीतियों एवं कार्यविधियों में भी, सबसे अधिक हित की बात पर सर्वसम्मति पाने के लिए भिन्न हितों का बीच बचाव करता है।

समता : सभी महिलाओं एवं पुरुषों को बेहतरी और अपनी खुशहाली बनाए रखने के लिए अवसर हों।

प्रभावकारिता एवं दक्षता : प्रक्रियाएं और संस्थाएं संसाधनों का श्रेष्ठ प्रयोग करते हुए, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले परिणाम उत्पन्न करती हैं।

उत्तरदायित्व : सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संस्थाओं में निर्णयकर्ता सार्वजनिक एवं संस्थागत दावेदारों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायित्व, संस्था और उसके लिए निर्णय आंतरिक है या बाहरी, इसके आधार पर यह अलग अलग होता है।

समान गुणों का सहभाजन करते हैं:

- महामारी से निपटने के लिए सबसे ऊँचे स्तर पर दृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता (इससे महामारी को संबोधित करने के लिए फण्ड तथा नीतियां सुनिश्चित हो जाती हैं)।
- रोकथाम व देखभाल के लिए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण और सरकार के स्तर पर बहुत से मंत्रियों की सहभागिता।

www.acmeme.org

सामरिक दूरदृष्टि : नेताओं तथा जनता का सुशासन और मानव विकास पर व्यापक और दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य होता है, साथ ही ऐसे विकास के लिए क्या चाहिए उसका भी आभास रहता है। जिन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जटिलताओं में प्ररिप्रेक्ष्य स्थापित होते हैं उनकी समझ भी होती है।

व्यवहार में सुशासन

कुछ देशों ने प्रभावकारी कार्यक्रम तैयार करने के लिए सुशासन के उपाय सम्मिलित किए हैं, जो एचआईवी/एड्स के प्रसार को रोकने में सफल रहे हैं। इन देशों में से हरेक में, राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम, वैश्विक रूप से बेहतरीन माने जाने वाले अभ्यासों के एक

- बहुस्तरीय प्रतिक्रियाएं (राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं समुदाय स्तर पर)
- महामारी और आचरणों की प्रभावकारी मॉनिटरिंग, और नीतियों एवं कार्यक्रमों को बेहतर बनाने तथा जागरुकता बनाए रखने दोनों, के लिए जाँच–परिणामों का वितरण।
- आम जनता और जोखिमपूर्ण समूहों पर फोकस करके एकसाथ मिलेजुले प्रयास।
- बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन।
- एकीकृत रोकथाम एवं देखभाल।